RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 269
दि. 31.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से फोन पर की बात, अमेरिकी दवाब के बीच किन मुद्दों पर बनी सहमति?

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यह बातचीत वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बाद हुई।

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और जनता के बीच संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी का विस्तार और गहराई से विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज ने दोनों देशों के आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और ग्लोबल साउथ के लिए उनके घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैंने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति, डेल्सी रोड्रिगेज से बात की।' पीएम मोदी ने बताया, 'हम सभी क्षेत्रों में अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा एवं व्यापक बनाने पर सहमत हुए हैं, ताकि आने वाले वर्षों में भारत-वेनेजुएला संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।'

अमेरिकी दबाव के बीच अहम है यह बातचीत

अमेरिकी दबाव के बीच पीएम मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई यह बातचीत काफी अहम है। इससे भारत-वेनेजुएला के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे, साथ ही भारत के पास ऊर्जा सुरक्षा में विकल्प बढ़ेगा।

दोनों नेताओं के बीच हुई यह बातचीत ट्रंप के दबाव के बीच भारत की स्वतंत्र कूटनीति का वाशिंगटन को सीधा संदेश है।

अमेरिकी नीतियों का भारत-वेनेजुएला दोनों पर असर

भारत और वेनेजुएला दोनों ही देश इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती नीतिओं के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। जहां एक ओर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। वहीं वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना पकड़कर उन्हें न्यूयॉर्क ले गई थी। जिसके बाद से ही वेनेजुएला में टेंशन का माहौल है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल भंडार पर अमेरिका अपना कब्जा करेगा।

डेल्सी रोड्रिगेज ने पांच जनवरी को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला था। यह घटनाक्रम अमेरिकी सेना द्वारा उनके पूर्ववर्ती मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाए जाने के दो दिन बाद हुआ।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज असम के धेमाजी में 10वें 'मिसिंग यूथ फेस्टिवल' को संबोधित किया

(एजेंसी)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज असम के धेमाजी में 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल को संबोधित किया। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा और केन्द्रीय मंत्री श्री सवार्नंद सोनोवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मिसिंग यूथ फेस्टिवल ने पूरे देश के ट्राइब्स को एक अलग दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों, संस्कृति, भाषा, साहित्य, नृत्य और संगीत की रक्षा करने का रास्ता हाथ में बंदूक लेकर नहीं बल्कि यूथ फेस्टिवल के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई संस्कृतियों को मिलाकर मिसिंग संस्कृति की तरह ही भारत की संस्कृति बनती है। श्री शाह ने कहा कि यह दृष्टिकोण आज असम को आगे ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊङ्गल्ल८-ढङ्ग'ङ्ग सिर्फ असम और अरुणाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत को दुनियाभर में प्रसिद्ध बनाती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में अलग अलग जनजातियां अपनी संस्कृतियों की रक्षा के लिए संघर्ष करती थीं और विपक्षी सरकारें इन सभी को कुचल कर रखना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त इंटरलॉक्यूटर सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का मानना है कि हर संस्कृति, भाषा, परंपरा को भारत में जीवित रहने का समान अधिकार है और इन सबके संवर्धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि बोगीबील ब्रिज की रचना हमारे मिसिंग श्रमिक भाईयों-बहनों के पसीने से हुई है। यह ब्रिज आज पूरे विश्व में नए भारत की कल्पना का प्रतीक बना है जिसे 4 साल में पूरा करने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मिसिंग समाज हमारे ब्रह्मपुत्र घाटी की धड़कन है। मिसिंग संस्कृति असम और भारत की संस्कृति की आत्मा, जीवंत पहचान और आने वाले भारत का एक प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिसिंग समाज के योगदान को भूल सकते। उन्होंने कहा कि हर संघर्ष में मिसिंग समाज ने भारत की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मिसिंग समाज ने नदियों को रास्ता देकर बाढ़ को कम करने का प्रयास किया है। श्री शाह ने कहा कि अली-आये-लिगांग प्रकृति के साथ संतुलन मिलाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (उअढऋ) में मिसिंग युवाओं की विशेष भर्ती भी होगी जिससे यहां के युवा भारत माता की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असम शांति के रास्ते पर चल रहा है। मोदी सरकार ने कई समझौते कर लगभग 10 हजार युवाओं के हाथ से हथियार छुड़ाए हैं। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने 200 लोअर प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग भाषा को शिक्षा के माध्यम से रूप में स्वीकार किया है। श्री शाह ने कहा कि आज असम का युवा ६ींस्रङ्गल्ल की जगह ५२ङ्गल्ल

भाजपा जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने सीएम योगी से मुलाकात की:बागपत के क्षेत्रीय मुद्दों और योजनाओं पर हुई चर्चा

बागपत के भाजपा जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र का गुड़ भेंट किया।

जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के साथ जिले में चल रही प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उन्हें पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाकर लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

भारत संपर्क - देश के युवाओं से संवाद: केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आईआईटी दिल्ली में छात्रों से बातचीत की

(एजेंसी)।

आउटरीच पहल 'भारत संपर्क—देश के युवाओं से संवाद' के तहत केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिसर का दौरा किया और छात्रों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।

(दिल्ली स्थित आईआईटी परिसर में छात्रों से बातचीत करते हुए मंत्री महोदय)

इस बातचीत के दौरान छात्रों ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रौद्योगिकी अपनाने, रसद, नवाचार, अनुसंधान सहयोग और सार्वजनिक संस्थानों में युवाओं की भागीदारी के अवसरों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा रूपांतरण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

छात्रों के करियर के अवसरों और सरकारी संस्थानों के साथ प्रत्यक्ष सहभागिता से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उन्नयन और संगठनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने रसद, नागरिक-केंद्रित सेवाओं, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवा वितरण में इंडिया पोस्ट की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया तथा छात्रों को इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट और नवाचार-संचालित सहयोग के माध्यम से विभाग से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।

नवाचार और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास से संबंधित प्रश्नों पर केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट भारत के तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स इकोसिस्टम, विशेष रूप से टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग देने के लिए अच्छी स्थिति में है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आईटी 2.0 आधुनिकीकरण परियोजना और डिजिटल प्रणालियों के तहत नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से इंडिया पोस्ट एक विश्वसनीय, भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक सेवा संस्थान के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया पोस्ट ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और उभरते व्यावसायिक अवसरों के अनुरूप नए, बाजार-संरेखित उत्पाद और सेवाएं भी पेश कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी दिल्ली स्थित अगली पीढ़ी वाले (नेक्स्ट जनरेशन) कैंपस डाकघर का भी दौरा किया, जो देश का पहला डाकघर है और इसे एन-जेन पहल के तहत नया रूप दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य कैंपस डाकघरों को आधुनिक बनाकर, उन्हें युवा-केंद्रित, डिजिटल रूप से सक्षम और छात्र-संचालित सेवा केंद्रों में बदलना है।

(मंत्री महोदय दिल्ली आईआईटी स्थित एन-जेन डाकघर में छात्रों से बातचीत करते हुए)

नए सिरे से तैयार किए गए एन-जेन कैंपस डाकघर में छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए आंतरिक सज्जा और कलाकृतियां, मुफ्त वाई-फाई, छात्रों के लिए समर्पित सेवा काउंटर, क्यूआर-आधारित बुकिंग और डिजिटल भुगतान, पार्सल पैकिंग की सुविधा और छात्रों के लिए रियायती स्पीड पोस्ट सेवाएं उपलब्ध हैं।

लखनऊ में गोमती तट पर सीएम योगी ने किया दीपदान, महात्मा गांधी और अमर शहीदों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

(एजेंसी)।

लखनऊ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित दीपदान एवं भजन-संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर भजन-संध्या में भाग लेते हुए दीपदान भी किया। उन्होंने महात्मा गांधी तथा स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान गांधीजी के प्रिय भजन 'रघुपति राघव राजा राम...' में स्वयं शामिल होकर मुख्यमंत्री ने गांधीजी के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

भारत ने चार वर्ष में आठ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रतिभा और व्यापार के लिए वैश्विक मौके पैदा हुए: श्री पीयूष गोयल

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दुनिया की एक तिहाई आबादी को कवर करता है और ग्लोबल जीडीपी के 25% हिस्से को प्रभावित करता है: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

चिली के साथ भारत के आगामी मुक्त व्यापार समझौते से महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बढ़ेगी: श्री पीयूष गोयल

वैश्विक अस्थिरता के बीच मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक्स मूलभूत सिद्धांतों के चलते भारत के निर्यात में बढ़ोतरी: श्री गोयल

184 शाखाओं में फैले 52 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट वैश्विक स्तर पर भारत की व्यावसायिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे: श्री गोयल

(एजेंसी)।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बात करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से आयोजित विश्व लेखा मंच को संबोधित करते हुए कहा कि यह समझौता लगभग एक तिहाई आबादी को कवर करता है, और ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करता है और वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा की ओर से भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को "सभी समझौतों की जननी" कहना कोई छोटी बात नहीं है।

यूरोपीय बाजार की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री गोयल ने कहा कि अकेले यूरोपीय संघ लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुएं और 3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की सेवाएं आयात करता है, जो मिलकर 10 ट्रिलियन डॉलर का बाजार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का वर्तमान निर्यात इस क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा भर है और इस विषय पर जोर दिया कि भारत के सामने अभूतपूर्व अवसर हैं, जिन्हें निश्चित रूप से भुनाया जाना चाहिए।

मंत्री जी ने कहा कि भारत ने बीते चार वर्ष में आठ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ देश की भागीदारी में एक आधारभूत बदलाव को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौते यूरोप और अन्य क्षेत्रों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं, जिनमें 27 देशों का यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और आइसलैंड से मिलकर बना चार देशों का ईएफटीए ब्लॉक, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।

गणतंत्र दिवस-2026 की परेड में संस्कृति मंत्रालय की 'वंदे मातरम - 150 वर्षों का सफर' नामक झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता

सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति 'वंदे मातरम: भारत की शाश्वत गूंज' को मिला विशेष पुरस्कार

(एजेंसी)।

गणतंत्र दिवस परेड-2026 में संस्कृति मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण दोहरा सम्मान प्राप्त किया, जहां उसकी "वंदे मातरम - 150 वर्षों का सफर" शीर्षक वाली झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बीच सर्वश्रेष्ठ झांकी की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वहीं उसकी भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति "वंदे मातरम: भारत की शाश्वत गूंज" को उसकी असाधारण कलात्मक और विषयगत उत्कृष्टता के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार विजेता झांकी ने वंदे मातरम के 150 वर्षों के सफर को सशक्त रूप से दशार्या, जिसमें राष्ट्रीय जागरण के गीत के रूप में इसके उद्भव और भारत के स्वतंत्रता संग्राम, एकता और सभ्यतागत चेतना को आकार देने में इसकी स्थायी भूमिका को दिखाया गया है। भावपूर्ण दृश्यों और प्रतीकों के माध्यम से, झांकी ने भारत की सामूहिक राष्ट्रीय पहचान में राष्ट्रगान की शाश्वत प्रासंगिकता को उजागर किया।

विशेष पुरस्कार विजेता सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति, 'वंदे मातरम - भारत की शाश्वत गूंज', का आयोजन संगीत नाटक अकादमी ने पटियाला स्थित उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से किया था। यह प्रस्तुति राष्ट्रऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर बनी। इस प्रस्तुति में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,500 कलाकारों ने भाग लिया और शास्त्रीय, लोक और आदिवासी कला रूपों के माध्यम से देश की विशाल सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया।

नृत्य प्रस्तुति ने देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और सशस्त्र बलों के शौर्य और समर्पण तक की शाश्वत यात्रा को जीवंत कर दिया। संस्कृत मंत्रों, भावपूर्ण संगीत और गतिशील नृत्य संरचनाओं से परिपूर्ण इस प्रस्तुति ने वंदे मातरम के संपूर्ण भावनात्मक और दार्शनिक पहलू को समाहित किया, जिसका समापन एकता, भक्ति और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हुआ।

संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा ने समग्र रचनात्मक निर्देशक के रूप में सांस्कृतिक प्रस्तुति का नेतृत्व किया। ऑस्कर विजेता संगीतकार श्री एम.एम. कीरावानी ने संगीत निर्देशन किया, जबकि गीत श्री सुभाष सहगल ने लिखे।

वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री 2026-27 के केंद्रीय बजट के बाद पूरे भारत के युवाओं के साथ संवाद करेंगी

2026-27 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 30 कॉलेज छात्रों के साथ संवाद करेंगी इस पहल के हिस्से के रूप में, कॉलेज छात्र लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट की लाइव प्रस्तुति को देखने का अवसर प्राप्त करेंगे, जो वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाहियों में से एक है। ये छात्र वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शिक्षा और विभिन्न राज्यों से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विविध शैक्षणिक अनुशासनों से हैं। छात्र वित्त मंत्रालय का भी दौरा करेंगे, जो कर्तव्य भवन-1 में स्थित है, वहां ये विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे ताकि मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण प्रक्रिया तथा राष्ट्र निर्माण में संस्थाओं की भूमिका को समझ सकें। शाम को बाद में, श्रीमती सीतारामन छात्रों के साथ संवाद करेंगी तथा बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं, भारत के भविष्य के लिए उसके दृष्टिकोण तथा युवाओं पर।

सम्पादकीय

अजीत पवार के जाने का महाराष्ट्र की राजनीति पर दूरगामी असर

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार को विमान दुर्घटना में मौत से जहां पूरा देश स्तब्ध है, शोक में डूबा हुआ है वहीं यह भी प्राश्न उठ रहा है कि उनकी अकस्मात मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? 66 साल के अजीत पवार का निजी विमान महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करते समय दुर्घटनाग्रास्त हो गया। बता दें कि अजीत पवार ने जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटा (एनसीपी) से बगावत कर दी थी। 2023 में 2 जुलाई को वे अपनी पाटा के 8 सदस्यों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे और सरकार में उपमुख्यमंत्री बने। शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के अपने फैसले पर अजीत पवार ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, इसलिए भाजपा के साथ वुछ मतभेद होने के बावजूद एनसीपी ने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। नवम्बर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और अजीत पवार अपने चाचा पर भारी पड़े। हालांकि छह महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पाटा को केवल एक सीट पर ही जीत मिली थी। तब अजीत पवार को महाराष्ट्र की सत्तारुढ़ भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में अजीत पवार सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरे। उन्होंने 41 विधानसभा सीटें हासिल की और लगभग अपने चाचा के विद्रोही गुट एनसीपी (एसपी) को खत्म कर दिया। जो केवल 10 सीटें ही जीत सकी। अजीत पवार ने 5 दिसम्बर 2024 को रिकार्ड छठी बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विश्लेषक कहते हैं कि शरद पवार की छाया में 20 साल बिताने के बाद अजीत पवार को लगा कि चाचा उनके रास्ते में बाधा बन रहे हैं इसलिए उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ़ लिया। 5 फरवरी से महाराष्ट्र जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के प्रचार के लिए अजीत दादा पवार बारामती जा रहे थे। एनसीपी का पूरा दायित्व अजीत पवार के ऊपर ही था। अजीत पवार का निधन तब हुआ है, जब शरद पवार राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। जिला परिषद के चुनाव में अजीत अपने चाचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे।

अब मुझे लग रहा है कि पूरी सहानुभूति शरद पवार के साथ जाएगी। भाजपा के उभार के बाद से महाराष्ट्र में मराठा नेताओं की हैसियत कमजोर हुई है और इसका अहसास प्रादेश में सबको है। मराठा जाति का वर्चस्व खेती, शिक्षा और बैंकिंग पर खत्म हो चुका है। शरद पवार के साथ अब मराठा जाति की सहानुभूति आएगी। ग्रामीण महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर अब भी मराठा जाति की पकड़ है और इन्हें अब लग रहा है कि भाजपा के आने से उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है।

देवेन्द्र फडणवीस की सरकार में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी अगर इस सरकार से हट जाती है तब भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले सरकार सत्ता में बनी रहेगी लेकिन फर्क दूसरी तरह से पड़ेगा। मराठा जाति अजीत पवार के निधन के बाद सोचेगी कि अब उनके पास कौन है? शरद पवार खुद ही जीवन के सांध्य काल में हैं। पूरा मराठा तबका अब सोचेगा कि उन्हें किस तरफ रुख करना है? एक विश्लेषक का कहना है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में हिन्दुत्व के बढ़ते प्राभाव के बीच अपनी ताकत बनाए हुए थे और यह बड़ी बात थी। भाजपा और शिवसेना दोनों हिन्दुत्व की राजनीति करते हैं। भाजपा की अगुवाई वाली सरकार स्थिर रहेगी लेकिन मराठा राजनीतिक का उभार हो सकता है। एनसीपी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट हो सकती है और यह भाजपा की मजबूती के हक में नहीं होगी। अजीत पवार को देवेन्द्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे की शक्ति संतुलन करने के रूप में भी देखा जाता था।

स्वराज की विचारधारा आज राष्ट्र निर्माण के संकल्प की प्रेरणास्रोत बनी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

राज्य के 2666 गाँवों को मिलेगा अपना ग्राम पंचायत घर

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करने का समारोह आयोजित हुआ

गुजरात की सभी ग्राम पंचायतों को उनका अपना पंचायत घर देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सेचुरेशन के विचार को साकार करने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री ने आणंद के भादरण से 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' लॉन्च की

ग्रामीण गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा की प्रेरक उपस्थिति

तहसील मुख्यालय हो और नगर पालिका न हो; ऐसे 114 गाँवों को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के प्रथम चरण में समाविष्ट किया जाएगा, ऐसे गाँवों को शहरी समकक्ष सुविधा मिलने से उनका गुणात्मक एवं सर्वांगीण विकास होगा

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- **आगामी समय में राज्य की 10 हज़ार से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों तक 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के विस्तार का लक्ष्य है**
- **इस योजना के जरिये ग्रामीण एवं शहरी विकास के बीच 'समग्र तथा संतुलित' विकास का विज़न 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से साकार होगा**
- **महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की विचारधारा आज राष्ट्र निर्माण के संकल्प की प्रेरणास्रोत बनी है**

गांधीनगर, 30 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को आणंद के भादरण में आयोजित समारोह से राज्य की 2666 ग्राम पंचायतों को उनके अपने ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए गाँवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो फोकस किया है, उसमें गुजरात अग्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का दिया गया सेचुरेशन अप्रोच गुजरात में साकार करने के लिए राज्य

सरकार ने आगामी दिवसों में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को उनके अपने पंचायत घर-सह-पटवारी आवास देने का महत्वाकांक्षी निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन 2666 गाँवों में कुल 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर से ही सरकारी सेवाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी।

उन्होंने इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' की राज्यव्यापी लॉन्चिंग भी की।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के 114 तहसील मुख्यालयों वाले ऐसे गाँव, जो तहसील मुख्यालय हैं; लेकिन नगर पालिका नहीं हैं, को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के प्रथम चरण में समाविष्ट कर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पानी, स्वच्छता, सोलर स्ट्रीट लाइट, ई-ग्राम, कम्युनिटी हॉल आदि शहरी समकक्ष आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

उन्होंने जोड़ा कि शहरों पर बोझ कम हो तथा शहरों जैसी सुविधाएँ गाँवों में मिलें; इस आशय से आगामी समय में राज्य में 10 हज़ार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' अंतर्गत लाने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी विकास के बीच अंतर घटेगा तथा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का प्रधानमंत्री का मंत्र समग्र एवं संतुलित विकास से साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकास की राजनीति को गति देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विज़नरी लीडरशिप का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास का स्केल व स्पीड बढ़े हैं। शहरों में बढ़ते शहरीकरण के दबाव को संतुलित करने के लिए ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखकर विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायतों के उत्थान के लिए केन्द्रित ऐसा कार्यक्रम राज्य में पहली बार आयोजित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत वर्षा जल संचय तथा भूमिगत जल रिचार्ज के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हर विधायक को 50 लाख रुपए का विशेष अनुदान आवंटित किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रिचार्जिंग व्यवस्थाएँ की जा सकें। मुख्यमंत्री ने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि अपनाने की अपील करते हुए सभी से भूमि का स्वास्थ्य सुधारने तथा भावी पीढ़ी को निरोगी भविष्य देने का संकल्प लेने को कहा।

30 जनवरी शहीद दिवस तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण

वर्षांत समीक्षा- 2025: डिजिटल न्याय, उपभोक्ता विश्वास और गुणवत्ता को बाजार में बढ़ावा देना

प्रमुख सुधार और उच्च प्रभाव वाली पहलें

(ई-जागृति, एनसीएच, बीआईएस मानक, कानूनी मेट्रोलॉजी सुधार)

ख. क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण

(एनटीएच, जागरूकता, मूल्य निगरानी, अवसंरचना)

प्रविष्टि तिथि: 30 खअठ 2026 4:29खट८ ढक्ह ऊै.

वर्ष 2025 के दौरान देश में उपभोक्ता संरक्षण ने गति, सुगमता और विश्वास की दिशा में निर्णायक प्रगति की इसलिए उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए एक निर्णायक दौर रहा। व्यापक डिजिटल परिवर्तन, बाजार स्थिरीकरण उपायों, आधुनिक मानकों और मजबूत संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से, विभाग ने उपभोक्ता कल्याण को भारत के विकसित होते बाजार के केंद्र बना रहना सुनिश्चित किया।

इस वर्ष कागज रहित उपभोक्ता अदालतों और एआई-सक्षम शिकायत निवारण से लेकर सुरक्षित घरेलू उत्पादों, सटीक व्यापार प्रथाओं और विस्तारित परीक्षण बुनियादी ढांचे तक, प्रतिक्रियात्मक विनियमन से उत्तरदायी, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन की ओर बदलाव देखने को मिला।

2025 पर एक नजर

ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर 2.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं।

1.31 लाख से अधिक उपभोक्ता मामलों का निपटारा डिजिटल माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से 27.61 करोड़ रुपये की राशि रिफंड की गई। देशभर में 575 केंद्रों पर दैनिक मूल्य निगरानी। कानूनी मापन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 12 जीएटीसी प्रमाणपत्र जारी किए गए। उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए बीआईएस मानक जारी किए गए। उपभोक्ता न्याय का डिजिटल रूपांतरण

ई-जागृति: गति, सरलता और सुलभताए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में 1 जनवरी 2025 को ई-जागृति का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया। यह एक देश में उपभोक्ता विवाद समाधान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एकीकृत, संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सीओएनएफओएनईटी, ई-दाखिल, ओसीएमएस और एनसीडीआरसी-सीएमएस जैसी पुरानी प्रणालियों को एकीकृत करके, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही इंटरफेस के तहत निर्बाध डिजिटल फाइलिंग, सुनवाई, केस प्रबंधन और निर्णयों को संभव बनाया गया है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई ई-जागृति ने बहुभाषी पहुंच, ओटीपी आधारित पंजीकरण, एन्क्रिप्टेड दस्तावेज आदान-प्रदान, वर्चुअल सुनवाई, वॉयस-टू-टेक्स्ट सहायता और वास्तविक समय में केस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्लेटफॉर्म के शुरू होने से व्यक्तिगत रूप से अदालतों में जाने, मुकदमेबाजी की लागत और प्रक्रियात्मक देरी को काफी कम हो गई है और इससे दूरदराज के स्थानों और विदेशों से भी उपभोक्ता न्याय सुलभ हो गया।

नवंबर 2025 के मध्य तक, 1,400 अनिवासी भारतीयों सहित 2.81 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया था, और अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से शिकायतें दर्ज की गई थीं। 1.35 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और 1.31 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। यह उपभोक्ता आयोगों में त्वरित निपटारे और लंबित मामलों में कमी को दर्शाता है।

प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और साप्ताहिक जनसुनवाई सत्र शुरू किए। यह वास्तविक समय में तकनीकी सहायता और शिकायत निवारण प्रदान करते हैं।

इस प्लेटफॉर्म ने उपभोक्ता विवादों को आगे बढ़ाने की लागत, समय और जटिलता को काफी हद तक कम कर दिया है, इससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को सुदृढ़ बनाना

डिजिटल सुधारों के साथ-साथ, विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत संस्थागत क्षमता को मजबूत करना जारी रखा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ग्रुप 'ए' पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को दक्षता और प्रशासनिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अधिसूचित किया गया।

विभाग ने वर्ष के दौरान उपभोक्ता आयोगों, उद्योग निकायों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और शिक्षाविदों को शामिल करते हुए कई हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें भी आयोजित कीं। इन परामर्श बैठकों का मुख्य उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित ऑनलाइन व्यापार तौर-तरीकों और न्याय की त्वरित डिलीवरी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था।

उपभोक्ता आयोगों को सुदृढ़ करने की योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए राज्यों को 7.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई।

उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार

2025 में उपभोक्ता जागरूकता पहलों का ध्यान व्यापकता, समावेशिता और सभी तक पहुंच पर केंद्रित था। प्रमुख अभियान "जागो ग्राहक जागो" डिजिटल, प्रिंट और आउटडोर प्लेटफॉर्म पर लगातार चलता रहा। इसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, सुरक्षित उपभोग तौर-तरीकों और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में शिक्षित किया गया।

स्मार्टफोन या स्थिर इंटरनेट सुविधा से वंचित नागरिकों तक पहुंचने के लिए विभाग ने देशव्यापी आईवीआरएस वॉयस कॉल अभियान और 11 भाषाओं में एसएमएस के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया।

भारत की एआई पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्थित रूप से विकसित हो रहा है: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले प्रमुख उपलब्धियों की घोषणा की गई

एमईआईटीवाई ने 60 अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों के विचारों सहित एआई के भविष्य पर एक संकलन का विमोचन किया

(एजेंसी)।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले एक उच्च स्तरीय संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने की। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अजय सूद और एमईआईटीवाई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए। संवाददाता सम्मेलन में प्रमुख घटनाक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, वैश्विक

भागीदारी की पुष्टि की गई तथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के संभावित परिणामों की झलक दिखाई गई। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया जाएगा जिसकी तैयारी चल रही है।

सभा को संबोधित करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है और यह वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन बनने वाला है। उन्होंने एआई वैल्यू चेन में काम कर रहे उद्योगपतियों, डेवलपर्स एवं इनोवेटर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया मुलाकातों का उल्लेख किया, जिनमें मॉडल, एप्लिकेशन एवं अवसंरचना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों से भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थित प्रगति एवं तैनाती-आधारित समाधानों पर मजबूत ध्यान केंद्रित होने का पता चलता है। मंत्री ने कहा कि प्रमुख आईटी कंपनियों ने 200 से अधिक विशिष्ट क्षेत्र-आधारित एआई मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान लॉन्च करने का प्रस्ताव है। उन्होंने आगे कहा कि एआई अवसंरचना में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश पहले से ही हो रहा है, जो समिट के समापन तक दोगुना हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 500 विश्वविद्यालयों में एआई अवसंरचना एवं उद्योग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का विस्तार करके एआई प्रतिभा विकास को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे इस क्षेत्र के लिए एक मजबूत प्रतिभा तैयार

श्री अश्विनी वैष्णव ने "द इम्पैक्ट एजेंडाः लीडरशिप रिफ्लेक्शंस" नामक एक संकलन का भी विमोचन किया, जिसमें एआई के भविष्य तथा समावेशी विकास, नवाचार एवं सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर लगभग 60 प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों के विचार शामिल हैं।

वेवएक्स ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मीडिया, मनोरंजन और उभरती प्रौद्योगिकी में एआई समाधानों पर फोकस करेगा

वेवएक्स एआई स्टार्टअप के लिए बिजनेस नेटवर्किंग और प्रदर्शनी का मंच प्रदान करेगा

(एजेंसी)।

वेवएक्स ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए स्टार्टअप उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह समिट इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाधानों को प्रदर्शित करने और भारत के तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच के रूप में काम करेगा।

समिट के हिस्से के तौर पर, वेवएक्स एक खास स्टार्टअप एग्जिबिशन प्रोग्राम आयोजित करेगा। इससे चुने हुए स्टार्टअप उद्यमों को अपने एआई-आधारित उत्पादों और समाधानों को देश-विदेश के अलग-अलग लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। एवीजीसी-एक्सआर सेगमेंट में काम करने वाले और एआई-आधारित उत्पादों पर काम कर रहे स्टार्टअप उद्यमों को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पवेलियन में खास शोकेस और बिजनेस नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पवेलियन मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में नवीनतम और उभरती हुई

एआई प्रौद्योगिकी को दिखाने के लिए एक सेंट्रल हब के तौर पर काम करेगा, जिससे इनोवेटर पॉलिसी बनाने वालों, इंडस्ट्री की हस्तियों, निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के साथ जुड़ सकेंगे, और सृजनात्मक और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

उम्मीद है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 स्टार्टअप उद्यमों और मुख्य हितधारकों के बीच व्यवस्थित जुड़ाव को बढ़ावा देकर भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

वेवएक्स के बारे में

वेवएक्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेव्स पहल के तहत एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म है, जो मीडिया, मनोरंजन और भाषा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में इनोवेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत की अगली पीढ़ी के सृजनात्मक और प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए लॉन्च किया गया, वेवएक्स इनोवेटर, सरकारी संस्थानों और इंडस्ट्री की हस्तियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है।

पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे के अंतर्गत संपर्क परियोजनाएं

(एजेंसी)।

अगरतला में दिसंबर, 2024 में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 72वीं पूर्ण बैठक के आयोजन के दौरान बनी सहमति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आठ उच्च-स्तरीय कार्य बलों का गठन किया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे (एनईईसी) पर एचएलटीएफ की अध्यक्षता मिजोरम के मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और असम, मेघालय और मणिपुर के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। एनईईसी पर एचएलटीएफ के जनादेश में, अन्य बातों के अलावा, एनईआर में मौजूदा आर्थिक बुनियादी ढांचे और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करना; कमियों की पहचान करना और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीतियाँ तैयार करना शामिल है। एनईईसी पर एचएलटीएफ की तीन बैठकें हो चुकी हैं।

'पीएम-डिवाइन' का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का तीव्र और समग्र विकास करना है:

बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं

क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाएं

कक्ष. क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को बढ़ाना, और

कव. विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कमियों को भरना

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, योजना के अंतर्गत शुरूआत से लेकर 21 जनवरी 2026 तक कुल 48 परियोजनाओं के लिए 6044.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की

योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/आईएएस की होती है। हालांकि, परियोजनाओं की निगरानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय तकनीकी सहायता इकाइयों, परियोजना गुणवत्ता निगरानी और थर्ड-पार्टी टेक्निकल इंस्पेक्शन एजेंसियों के माध्यम से और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी परिषद के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के साथ-साथ समीक्षा बैठकों के दौरान भी की जाती है। उपरोक्त एजेंसियों की निरीक्षण रिपोर्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीएस) पोर्टल पर परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी के लिए अपलोड की जाती है। ऊपर दी गई जानकारी के अलावा, एफटीएसयू आईएएस के साथ मिलकर काम करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर परियोजना की प्रगति को अपडेट करते हैं।

'जिलों के सर्वांगीण विकास' थीम पर नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज 2025-26 का 34वां वेबिनार

नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज 2025-26 का 34वां वेबिनार 'जिलों के सर्वांगीण विकास' थीम पर 30 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा किया गया और उन्हें दोहराने पर चर्चा हुई

गुमला जिले की पहल, पूर्वी सिंहभूम पर कर्ण सत्यार्थी और कारगिल जिले की पहल, लद्दाख पर श्रीकांत बालासाहेब सुसे ने राष्ट्र के दर्शकों के सामने प्रस्तुति दी

प्रविष्टि तिथि: 30 खअठ 2026 5:31खट८ ढक्ह ऊै.

प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पिछले विजेताओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि उनका और भी अधिक प्रचार-प्रसार और दोहराव हो सके।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, डीएआरपीजी ने अप्रैल, 2022 से हर

महीने एक वेबिनार के हिसाब से 34 नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार आयोजित किए हैं, ताकि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकन का प्रचार-प्रसार और दोहराव को बढ़ावा दिया जा सके। हर वेबिनार में लाइन विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी शामिल होते हैं।

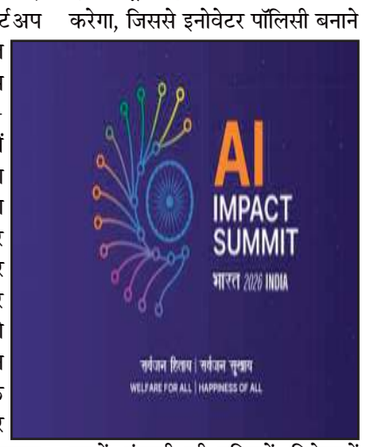

ये वेबिनार न सिर्फ पहल के संस्थागतकरण/स्थिरता की मौजूदा स्थिति बताते हैं, बल्कि इसके दोहराव/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी देते हैं।

34वां वेबिनार 30 जनवरी, 2026 को हुआ, जिसमें 2023 के लिए 'जिलों के समग्र विकास' थीम के तहत प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों ने, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पावर पॉइंट प्रस्तुति दी:

गुमला जिला पहल, झारखंड, जिसे कर्ण सत्यार्थी, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड ने प्रस्तुत किया; और

कारगिल जिला पहल, लद्दाख, जिसे श्रीकांत बालासाहेब सुसे, उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर ने प्रस्तुत किया।

वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के अपर सचिव पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में पूरे भारत में 600 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिले के अधिकारियों, केंद्र और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com•garvigujarat2007@yahoo.com•Website : www.garvigujarat.co.in

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को विधिवत संभालते हुए

महाप्रबंधक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे : श्री प्रदीप कुमार

मुंबई, 30 जनवरी, 2026

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार 29 जनवरी, 2026 से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री प्रदीप कुमार भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा (IRSME) के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको भारतीय रेल में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

अपने सेवाकाल के दौरान आपने पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे (SER), ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) सहित विभिन्न जोनल रेलों पर महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदार पदों पर कार्य किया है।

श्री प्रदीप कुमार ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं, जिनमें कैरिज वर्कशॉप, अजमेर में प्रोडक्शन इंजीनियर; कोटा में मंडल यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज एवं वैगन); वडोदरा में मंडल यांत्रिक इंजीनियर; पश्चिम रेलवे में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (योजना), उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (वर्कशॉप) तथा मुंबई के कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपने कोटा के वैगन रिपेयर शॉप में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (मरम्मत) तथा वरिष्ठ ईडीपीएम के रूप में भी कार्य किया है।

श्री कुमार ने कई महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी पदों पर भी कार्य किया है, जिनमें दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता में मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर; भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान (IRIMEE), जमालपुर में वरिष्ठ प्रोफेसर; ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी के पद शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा विरार-सूरत-वडोदरा खंड पर कवच 4.0 का कमीशन

मुंबई, 30 जनवरी, 2026

यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए पश्चिम रेलवे ने 344 किलोमीटर लंबे विरार-सूरत-वडोदरा खंड पर यात्री ट्रेनों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन संरक्षण प्रणाली कवच संस्करण 4.0 को कमीशन कर दिया है। 30 जनवरी, 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई, जब ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सायाजीनगरी एक्सप्रेस मुंबई से चलने वाली पहली कवच-सुसज्जित ट्रेन बनी। यह पश्चिम रेलवे नेटवर्क पर उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विरार-सूरत-वडोदरा खंड के 344 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कवच प्रौद्योगिकी को कमीशन किया गया है। इस कॉरिडोर पर कवच को 49 स्टेशनों पर लागू किया गया है, जिसे 57 रेडियो संचार टावरों तथा लगभग 700 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का सहयोग प्राप्त है। कवच एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, जो सिगनल का खतरे की स्थिति में पार होना, अधिक गति तथा टक्करों जैसी मानवीय त्रुटियों से उत्पन्न जोखिमों को न्यूनतम करने में सहायक है। साथ ही, लेवल क्रॉसिंग पर स्वचालित सीटी (ऑटो-व्हिसलिंग) और लोको पायलट के केबिन में सिगनल पहलू की पुनरावृत्ति जैसी विशेषताओं के माध्यम से प्रतिकूल मौसम और कम दृश्यता की परिस्थितियों में भी परिचालन सुरक्षा को और सुदृढ़ करता है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (कार्यवाहक) श्री प्रदीप कुमार, पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दादर (पश्चिम रेलवे) स्टेशन पर कवच संस्करण 4.0 के कमीशनिंग के अवसर पर। (दाएँ) ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सायाजीनगरी एक्सप्रेस के लोकोमोटिव में स्थापित कवच उपकरण। दाहिने तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रणाली के कार्य-प्रणाली का व्याख्यात्मक चित्र, जिसमें स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के लिए ऑनबोर्ड, ट्रैकसाइड तथा स्टेशन-स्तरीय घटकों के निर्बाध एकीकरण को दशार्या गया है।

पश्चिम रेलवे द्वारा इससे पूर्व दिसम्बर 2025 में वडोदरा-अहमदाबाद खंड पर कवच प्रणाली को कमीशन किया गया था। विरार-वडोदरा खंड के कमीशन होने के साथ ही, वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर कुल 435 रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है।

श्री विनीत ने आगे कहा कि भारतीय रेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रौद्योगिकी एक तकनीकी रूप से उन्नत एवं लागत-प्रभावी सुरक्षा समाधान है, जो रेलवे सुरक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है।

पहले से कमीशन किए गए खंडों के अतिरिक्त, पश्चिम रेलवे के 2667 रूट किलोमीटर को कवर करने वाले अन्य कई खंडों पर कवच कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹1435 करोड़ है। इसके अलावा, 2476 मार्ग किलोमीटर पर कवच कार्यों के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किए गए हैं, जो इस कार्यक्रम के व्यापक स्तर और तीव्र गति को दशार्ते हैं। चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ, पश्चिम रेलवे अपने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क पर कवच के विस्तार की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे समग्र रेल

इंडिया एनर्जी वीक (क्एह)2026 का समापनः भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा नेतृत्व की मजबूत पुष्टि और नवाचार उत्कृष्टता की मान्यता

केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की तैयारियों, लचीलापन और बढ़ते वैश्विक ऊर्जा प्रभाव को रेखांकित किया

(एजेंसी)।

भारत ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में निरंतर भू-राजनीतिक अस्थिरता का सामना करने के लिए मजबूत तैयारियां प्रदर्शित की हैं और वैश्विक ऊर्जा संवाद के केंद्र में दृढ़ता से बने रहने का संकल्प लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक (क्एह) 2026 के समापन समारोह में ये बात कही।समापन फायरसाइड चैट के दौरान बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि भारत की ऊर्जा रणनीति विविधीकरण, लचीलापन और भविष्योन्मुखी संक्रमण पर आधारित है। 'भारत ने लगातार भू-राजनीतिक झटकों का बहुत अच्छे से सामना किया है। श्री पुरी ने कहा कि आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण और स्वच्छ ईंधनों की ओर तेजी से संक्रमण के माध्यम से,' हर चुनौती को अवसर में बदल दिया गया है— भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति को रेखांकित करते हुए, उन्होंने नोट किया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है।

उन्होंने जोड़ा 'भारत वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी ऊर्जा की उपलब्धता, किफायतीपन और स्थिरता सुनिश्चित करता रहेगा,' ।

मंत्री के बाद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने भारत की 7 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए सरकार की रूपरेखा का वर्णन किया। उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को मजबूत करने पर जोर दिया, साथ ही भारत को परिष्कृत उत्पादों का विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने पर भी। डॉ. मित्तल ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में संचालन दक्षता और लचीलापन सुधारने में डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लॉजिस्टिक्स अनुकूलन की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया।

समापन दिवस पर क्एह 2026 का समापन भी चिह्नित किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स, अकादमिया और उद्योग में नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और नेतृत्व को मान्यता देने वाले पुरस्कार प्रदान किए गए।

अविन्या – द एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज के तहत, मिनीमाइन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस विजेता के रूप में उभरा,

ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देने वाले पुरस्कारों के साथ भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का समापन

स्वच्छ ऊर्जा, अपस्ट्रीम प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में योगदान के लिए प्रतिनिधियों और नवप्रवर्तकों को सम्मानित किया गया

(एजेंसी)।

भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में देश के ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाले नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। 27 से 30 जनवरी, 2026 तक गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन ने वैश्विक ऊर्जा इकोसिस्ट टम में भारत की केंद्रीय भूमिका को उजागर किया, साथ ही नीति निमार्ताओं, व्यापार जगत, नवप्रवर्तकों और निवेशकों को एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा भविष्य के लिए व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट किया।

अविन्या – ऊर्जा स्टार्टअप चुनौती

अविन्या चैलेंज ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करने वाले उभरते भारतीय स्टार्टअप्स को मान्यता दीः

विजेताः मिनिमिन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस – श्री हार्दिक और श्री अनुपम कुमार को एचएचएम प्रक्रिया के लिए सम्मानित किया गया है, जो ईओएल वाली लिथियम-आयन बैटरियों से उच्च-मूल्य वाली सामग्रियों की कम कार्बन वाली रिकवरी प्रदान करती है, और इसका सौर पैनलों, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स और स्थायी चुंबकों में विस्तार जारी है।

प्रथम उपविजेताः ओससं बायोरेन्यूएबल्स – डॉ. सुरुचि राव, श्री कमर सुहैल बाशा, औद्योगिक अपशिष्ट जल को हरित हाइड्रोजन में परिवर्तित करने की उनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया के लिए।

द्वितीय उपविजेताः ट्रान्जमेओ

आईटी सॉल्यूशंस – श्री सफिल सनी, श्री राकेश मिश्रा, जिन्होंने एआई-संचालित फाइबर-सेंसिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से पाइपलाइनों, वेंट और सीसीयूएस प्रक्रियाओं की सटीक निगरानी को सक्षम बनाया।

तीसरा उपविजेताः रेजलिटिक्स टेक्नोलॉजीज – श्री दीपशंकर नंदा, श्री विनय भारद्वाज, जिन्होंने एआई-संचालित डीप इन्फॉर्मेशन मैक्सिमाइजेशन इंजन विकसित किया है जो तेल और गैस अन्वेषण में क्रांति ला रहा है।

चौथा उपविजेताः पेट्रोबोट टेक्नोलॉजीज – श्री साहब गुर्जर, श्री शशि फागना, हाइड्रोकार्बन संयंत्रों और जहाजों में रोबोटिक निरीक्षण समाधान के लिए।

वसुधा – ओवरसीज अपस्ट्रीम स्टार्टअप चैलेंज

इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता ने अपस्ट्रीम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाले स्टार्टअप्स को मान्यता दीः

ँ३३स्र२://२३३.स्रु.ड्ढ५.ल्ल/ह१३ी फींड्ढ/४रीथ्र१२/११003टफ्8ढ.स्र्

विजेताः सेनेर्जेटिक्स, नीदरलैंड्स – श्री फ्रांसिस्कस जोहाना जैकब्स, सुश्री अनीता, एआई-संचालित संक्षारण निगरानी के लिए, जो सुरक्षित और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करती है।

उपविजेताः रेसरमाइन इंक, यूएसए – श्री एंटोन माल्कोव, श्री अमित कुमार, जलाशय इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो को अनुकूलित करने वाले हॉकआई हाइब्रिड मॉडल इंजन के लिए।

हैकाथॉन चैलेंज

इसमें सात प्रमुख संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें ऊर्जा प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषी समस्या-समाधान को मान्यता देने वाले पुरस्कार शामिल थेः

ँ३३स्र२://२३३.स्रु.ड्ढ५.ल्ल/ह१३ी फींड्ढ/४रीथ्र१२/११004192.स्र्

विजेताः आईआईटी बॉम्बे – सौतिक भक्ता, प्रोफेसर कुमार हेमंत सिंह, जिन्होंने ऑरा नामक एक एआई-संचालित एकीकृत जलाशय विश्लेषण मंच विकसित किया है, जो अर्ध-पर्यवेक्षित सीएनएन ट्रांसफार्मर फ्रेमवर्क का उपयोग करता है।

उपविजेताः आईआईटी दिल्ली – स्वागत सब्यसाची साहू, अक्षत अग्रवाल, मनोग्या सुनील चोरडिया, देबरुन बनर्जी, प्रोफेसर विक्रांत, जिन्होंने इस्पात उद्योग के स्लैग के माध्यम से द्वि-क्षारीय विलायक-आधारित सीओ$_2$ कैप्चर और खनिजकरण का उपयोग करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण अपनाया।

एफआईपीआई / आईआईपी वार्षिक उद्योग पुरस्कार

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ ने अन्वेषण, उत्पादन, शोधन, नवाचार और गैस वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को सम्मानित किया।

ँ३३स्र२://२३३.स्रु.ड्ढ५.ल्ल/ह१३ी फींड्ढ/४रीथ्र१२/११005टह1श्.स्र्

वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण कंपनीः ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) – कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई।

वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी (1 मिलियन वर्ष से अधिक उत्पादन)ः ऑयल इंडिया लिमिटेड – उन्नत रिकवरी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादन में नेतृत्व के लिए सम्मानित।

रक्षा राज्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और सर्वश्रेष्ठ झांकी को पुरस्कार प्रदान किए

26 जनवरी का दिन विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति राष्ट्र के संकल्प की पुष्टि करता हैः श्री संजय सेठ

(एजेंसी)।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 30 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस परेड-2026 के अंतर्गत तीनों सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/अन्य सहायक बलों की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कार प्रदान किए। रक्षा राज्य मंत्री ने परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को बधाई दी और इस बात पर बल दिया कि 26 जनवरी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति राष्ट्र के संकल्प की पुनः पुष्टि का प्रतीक है। रक्षा राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री की उस अपील को भी दोहराया, जो पीएम एनसीसी रैली-2026 के दौरान युवाओं से की गई थी, जिसमें प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक घंटा स्वच्छता अभियान हेतु समर्पित करने और किसी चयनित स्थान पर गतिविधि आयोजित करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने स्वच्छता को पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी बताया।

टुकड़ियों एवं झांकियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए गठित तीन न्यायाधीश पैनलों द्वारा निम्नलिखित टुकड़ियों और झांकियों का चयन किया गयाः

- तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता – भारतीय नौसेना
- सीएपीएफ/अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता – दिल्ली पुलिस
- शीर्ष तीन झांकियां (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)ः

महाराष्ट्र (गणेशोत्सवः आत्मनिर्भरता का प्रतीक)

2. जम्मू – कश्मीर (जम्मू – कश्मीर के हस्तशिल्प एवं लोक नृत्य)

3. केरल (वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरताः आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल)

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी – संस्कृति मंत्रालय (वंदे मातरम – राष्ट्र की अन्तरात्मा की पुकार)

विशेष पुरस्कारः

1. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (वंदे मातरम – 150 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव)

2. 'वंदे मातरमः भारत की शाश्वत गूंज' नृत्य समूह

नागरिकों द्वारा अपनी पसंदीदा झांकी और परेड दस्ते के लिए मायगॉव पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन मतदान के आधार पर 'लोकप्रिय पसंद' श्रेणी के परिणाम इस प्रकार हैंः

- तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता – असम रेजिमेंट

भारत भू-राजनीतिक बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार

इंडिया एनर्जी वीक 2026 का समापन, भारत ने ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में अपनी भूमिका को और मजबूत किया

भारत भू-राजनीतिक बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार है और ग्लोबल एनर्जी डायलॉग में केंद्र में बना हुआ हैः केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी

घरेलू खोज, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और स्थिर कीमतें भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करती हैं

(एजेंसी)।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2026 के समापन समारोह में कहा कि भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में लगातार भू-राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत तैयारी दिखाई है और इंटरनेशनल एनर्जी डायलॉग में केंद्र में बना रहेगा। यह कार्यक्रम 27 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 तक गोवा में आयोजित किया गया।

समापन फायरसाइड चैट के दौरान बोलते हुए, श्री पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की एनर्जी रणनीति विविधीकरण, सशक्तता और भविष्य के अनुकूल बदलावों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमने लगातार भू-राजनीतिक झटकों का बहुत अच्छे से सामना किया है। सप्लाई के सोर्स के विविधीकरण और क्लीनर फ्यूल की ओर तेजी से बदलाव के जरिए हर चुनौती को एक अवसर में बदला गया है।"

भारत के वैश्विक रुख से अवगत कराते हुए, श्री पुरी ने कहा कि आज देश तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। श्री पुरी ने कहा, "ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी, भारत एनर्जी की उपलब्धता, किफायती दाम और सततता सुनिश्चित करता रहेगा।"

केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक ईंधनों में लगातार निवेश के साथ-साथ कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन और स्वदेशी क्लीन-एनर्जी टेक्नोलॉजी पर सरकार द्वारा जोर दिये जाने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "पारंपरिक एनर्जी जरूरी रहेगी, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर सीबीजी, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल तक हम जो कदम उठा रहे हैं, वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि ग्रीनर फ्यूल एक बड़ी भूमिका निभाएंगे।"

वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए, श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों को अस्थिरता से सफलतापूर्वक बचाया है। उन्होंने कहा, "वैश्विक उथल-पुथल का असर कभी भी उपभोक्ता पर नहीं पड़ा। आज भारत में एनर्जी की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं और संकट के समय भी बिना किसी रुकावट के आपूर्ति बनाए रखी गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा समय पर कार्रवाई के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि एलपीजी सहित फ्यूल की कीमतें उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनी रहें।"

श्री पुरी के बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने भारत की विकास यात्रा को समर्थन करने के लिए

भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए कवच 4.0 का विस्तार तेज किया, तीन खंडों में 472 किमी मार्ग पर शुरूआत

एक ही दिन में कवच की अब तक की सबसे बड़ी कमीशनिंग हासिल की गई

वडोदरा-विरार (344 किमी), तुगलकाबाद जंक्शन केबिन-पलवल (35 किमी) और मानपुर-सरमतनार (93.3 किमी) खंडों पर कवच 4.0 की शुरूआत हुई

कवच 4.0 अब भारतीय रेलवे के पांच जोन में 1,300 से अधिक रूट किलोमीटर को कवर करता है

(एजेंसी)।

भारतीय रेलवे ने आज अपने नेटवर्क के तीन खंडों में 472.3 रूट किलोमीटर पर कवच वर्ज़न 4.0 (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली) की शुरूआत की, जो रेल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और

महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नए कमीशन किए गए खंडों में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा-विरार (344 किमी), उत्तर रेलवे पर तुगलकाबाद जंक्शन केबिन-पलवल (35 किमी) और पूर्व मध्य रेलवे पर मानपुर-सरमतनार (93.3 किमी) शामिल हैं। इस शुरूआत के साथ, भारतीय रेलवे उच्च-घनत्व वाले मार्गों पर ट्रेन सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कवच प्रणाली की तैनाती को तेज करना जारी रखे हुए है।

यह उपलब्धि एक ही दिन और साथ ही एक महीने में कवच कमीशनिंग के अब तक के सबसे अधिक रूट किलोमीटर का रिकॉर्ड है, जिसमें 472.3 आर किमी को कवच वर्ज़न 4.0 के दायरे में लाया गया है। इससे पहले सबसे बड़ी कमीशनिंग पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा-मथुरा खंड पर 324 आर किमी थी। इस

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशाखापत्तनम में 32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीएसआईआर-एनआईओ के तटवर्ती क्षेत्रीय केन्द्र का उद्घाटन किया

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशाखापत्तनम में 32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीएसआईआर-एनआईओ के तटवर्ती क्षेत्रीय केन्द्र का उद्घाटन किया

यह परियोजना 20 वर्षों तक विलंबित रही, लेकिन राज्य में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही पूरी हो गई; इस प्रकार यह 'दोहरे इंजन के प्रभाव' का प्रमाण हैः केन्द्रीय मंत्री

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'नीली अर्थव्यवस्था' और समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दिए जाने पर प्रकाश डाला

सीएसआईआर-एनआईओ की नई सुविधा से भारत के समुद्री विज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा और तटीय सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलेगाः डॉ. जितेंद्र सिंह

सीएसआईआर-एनआईओ का विशाखापत्तनम केन्द्र अपतटीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जलवायु संबंधी अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

पूर्वी महाद्वीपीय सीमांत से संबंधित अनुसंधान से तेल, गैस और समुद्री खनिजों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होगीः डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रविष्टि तिथिः 30 खअठ 2026 5:20ढट८ ढक्ह ऊे

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज विशाखापत्तनम स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) के क्षेत्रीय केन्द्र की तटवर्ती प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और इसे 'दोहरे इंजन वाली सरकार के प्रभाव', जहां केन्द्र और राज्य के बीच का निर्बाध समन्वय विकास को गति देता है, का स्पष्ट उदाहरण बताया।

आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री श्रीमती अनीता वंगलपुडी, सांसद श्री एम. श्रीभरत, विधायक श्री जी. श्रीनिवास राव, सीएसआईआर-एनआईओ के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह,

डॉ. वी.वी.एस.एस. शर्मा और सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. कलैसेल्वी की उपस्थिति में सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही इस परियोजना की नींव वर्षों पहले रखी गई थी, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारों के एकमत होने के बाद पिछले 8-10 महीनों में इसमें काफी प्रगति हुई और यह पूरी हो गई।

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा 2000 के दशक के आरंभ में नाममात्र की कीमत पर हस्तांतरित की गई थी और इस क्षेत्र में हुए तीव्र विकास के कारण इसका वर्तमान मूल्य कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, सीएसआईआर और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (जो सीएसआईआर के अध्यक्ष हैं) की ओर से, कुल 32 करोड़ रुपये की इस तटवर्ती परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर रही है।

इस सुविधा के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की तटरेखा लगभग 11,000-12,000 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 1,000 किलोमीटर से अधिक आंध्र प्रदेश से लगती है, जो इसे समुद्री अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री के 'नीली अर्थव्यवस्था' से संबंधित विजन का एक स्वाभाविक केन्द्र बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वी तटीय सीमांत भूवैज्ञानिक रूप से विविधतापूर्ण है और इसमें मुख्य रूप से हिमालयी नदी प्रणालियों द्वारा भारी मात्रा में निक्षेपित हाइड्रोकार्बन, समुद्री खनिजों, तेल और प्राकृतिक गैस की अपार संभावनाएं हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम तट एक बहुमुखी समुद्री संसाधन आधार का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और नव उद्घाटित सीएसआईआर-एनआईओ सुविधा इस प्रयास के एक प्रमुख वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य करेगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीएसआईआर-एनआईओ पहले से ही ओएनजीसी, ऑयल इंडिया तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है और फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाहों, तापीय ऊर्जा परियोजनाओं व मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को सक्रिय रूप से सहयोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि संभावित मछली पकड़ने वले क्षेत्रों की पहचान, मछुआरों के लिए समुद्री शैवाल की खेती और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की भविष्यवाणी करने से संबंधित केन्द्र सरकार के कार्यों से आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ हो रहा है, क्योंकि समुद्री जैव संसाधनों का उपयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है।

सरकार की समन्वित दृष्टि पर जोर देते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री विकास अब केन्द्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप को एक साथ ला रहा है। उन्होंने उद्योग जगत और उद्यमियों को सक्रिय साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि समुद्री एवं तटीय क्षेत्र में स्टार्टअप व नवोन्मेषकों के लिए तकनीकी तथा वित्तीय समर्थन का एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही मौजूद है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशाखापत्तनम केन्द्र क्षमता विकास और कौशल प्रशिक्षण के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी उभरेगा, जो देश के बढ़ते समुद्री क्षेत्र के लिए युवा वैज्ञानिकों, शोधकताओं, स्टार्टअप और भावी उद्यमियों का मार्गदर्शन करेगा।

तय हो गया है कि सुनेत्रा पवार ही प्रदेश की नई डिप्टी सीएम होंगी, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी तय

(एजेंसी)।

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के आकस्मिक निधन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, अब यह तय हो गया है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ही प्रदेश की नई डिप्टी सीएम होंगी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है। शनिवार को उनका शपथ ग्रहण होगा।

बताया जा रहा है कि वे शनिवार को शपथ ले सकती हैं। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर शुक्रवार को बारामती में एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और जय पवार के साथ पारिवारिक सलाहकार नरेश अरोड़ा मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस

फैसले की सूचना बीजेपी को भी दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, शनिवार को सुबह 11 बजे के बाद विधानभवन में एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में औपचारिक तौर पर सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिलहाल वह राज्यसभा की सांसद हैं।

अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह अजित पवार की सीट से ही चुनाव लड़ेंगी या फिर विधान परिषद की सदस्यता लेंगी। बताया जा रहा है कि दोपहर में वे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। शपथ समारोह को लेकर राजभवन को औपचारिक सूचना दिए जाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।

इस राजनीतिक बदलाव के साथ ही एनसीपी संगठन में भी बड़ा फेरबदल संभव है। जानकारी के मुताबिक, प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

भारतीय वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा चलने वाला स्व-चार्जिंग ऊर्जा भंडारण उपकरण विकसित किया है

(एजेंसी)।

वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फोटो-कैपेसिटर नामक अभिनव सौर ऊर्जा-संचालित सुपरकैपेसिटर एक ही एकीकृत उपकरण में सौर ऊर्जा को लेने और उसे संग्रहीत करने के दोनों काम कर सकता है।

यह स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम हो सकता है, जो कही ले जाने तथा पहनने योग्य और ऑफ ग्रिड प्रौद्योगिकियों के लिए कुशल, कम लागत वाले और पर्यावरण के अनुकूल बिजली समाधानों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

परंपरागत रूप से, सौर ऊर्जा प्रणालियां दो अलग-अलग इकाइयों पर निर्भर करती हैं: ऊर्जा संग्रहण के लिए सौर पैनल और ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी या सुपरकैपेसिटर। यद्यपि ऐसी हाइब्रिड प्रणालियां बड़े पैमाने के सौर फार्मों से लेकर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, फिर भी ऊर्जा संग्रहण इकाई और भंडारण इकाई के बीच वोल्टेज और करंट के असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए इनमें अतिरिक्त विद्युत प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने से प्रणाली की जटिलता, लागत, ऊर्जा हानि और उपकरण का आकार बढ़ जाता है, जो विशेष रूप से लघु और स्वायत्त उपकरणों के लिए हानिकारक साबित होता है।

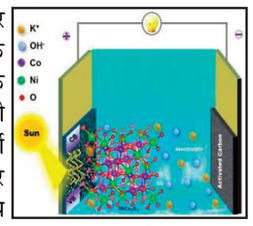

सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (सीईएनएस), बेंगलुरु द्वारा विकसित इस नए फोटो-रिचार्जेबल सुपरकैपेसिटर ने सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने और उस ऊर्जा को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करने की दोनों प्रक्रियाओं को सहजता से संयोजित किया है। इससे डिजाइन सरल हो जाता है और रूपांतरण तथा भंडारण के दौरान ऊर्जा हानि कम से कम हो जाती है।

डॉ. कविता पांडे के मार्गदर्शन में, बाइंडर-मुक्त निकल-कोबाल्ट ऑक्साइड (ढ्ढउङ्ग 2 ड 4) नैनोवायरों के उपयोग की मदद से नवाचार किया गया है। इन्हें एक सरल इन सीटू हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया का उपयोग करके निकल फोम पर समान रूप से तैयार किया गया है।

केवल कुछ नैनोमीटर और लंबाई कई माइक्रोमीटर व्यास वाले ये नैनोवायर अत्यंत छिद्रपूर्ण और सुचालक 3डी नेटवर्क बनाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को कुशलतापूर्वक अवशोषित करता है और विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। इस अनूठी संरचना के कारण यह पदार्थ एक साथ सौर ऊर्जा संग्राहक और

भोपाल में ओबीसी आरक्षण 'होल्ड' पर भड़का आक्रोश: 27% लागू करने की मांग को लेकर विशाल आंदोलन

(एजेंसी)।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज सामाजिक न्याय की एकजुट आवाज से गूंज उठी। राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के नेतृत्व में 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड को तत्काल समाप्त कर पूर्ण 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर एक विशाल संयुक्त आंदोलन आयोजित किया गया।

प्रदेशभर से हजारों ओबीसी युवा, अभ्यर्थी और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन गुर्जर समाज, भीम आर्मी, एससी-एसटी-ओबीसी महासभा, उद्धरर (दलित-पिछड़ा संघर्ष समिति) सहित कई संगठनों का संयुक्त मोर्चा था।

आंदोलनकारियों ने भोपाल के

प्रमुख स्थानों से मार्च निकाला और मोहन यादव सरकार पर जमकर बरसे। मुख्य वक्ता दामोदर यादव मंडल (संस्थापक उद्धरर एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य) ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "यह सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं, संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 46 का सीधा उल्लंघन है। 13% होल्ड अभ्यर्थी 6 साल से अधर में लटके हैं। मोहन सरकार की मनुवादी सोच अब बर्दाश्त नहीं होगी। जल्द से जल्द होल्ड खत्म कर न्याय दो, वरना यह लड़ाई जारी रहेगी और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे!"

क्या है 13% होल्ड का पूरा मामला?

मध्य प्रदेश में ओबीसी को संवैधानिक रूप से 27% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन पिछले कई वर्षों से विभिन्न भर्तियों (शिक्षा, नौकरी, प्रमोशन) में 13% पदों को 'होल्ड' (रोक) कर रखा गया है। कारण: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित याचिकाएं, जहां रोस्टर, जनसंख्या आंकड़े और अन्य मुद्दों पर विवाद है। सरकार भर्ती विज्ञापनों में 27% देती है, लेकिन वास्तव में केवल 14% लागू हो पाता है-बाकी 13% होल्ड पर अटका रहता है।

तीव्र भूचुंबकीय तूफान ने अंतरिक्ष मौसम पर होने वाले सूक्ष्म सौर सीएमई के प्रभाव को दशार्या

(एजेंसी)।

खगोलविदों ने मार्च 2023 में सूर्य से चल कर पृथ्वी तक आए कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) का अध्ययन किया है। इसके सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में मौजूद छिद्र (कोरोनल होल) से होकर गुजरने के दौरान सौर पवन धाराओं का रिसाव हुआ। इस अध्ययन में बताया गया है कि कैसे एक सूक्ष्म सौर सीएमई पृथ्वी पर तीव्र भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न कर सकता है और इससे अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों का पूवार्नुमान लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) सूर्य के वायुमंडल से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों का शक्तिशाली निष्कासन है जो कभी-कभी तीव्र भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। इससे पृथ्वी पर उपग्रहों, संचार प्रणालियों और बिजली ग्रिडों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

हालांकि, लगभग 10 प्रतिशत तीव्र भूचुंबकीय तूफान सौर डिस्क पर किसी बड़े पैमाने के विस्फोट से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि कमजोर या गुप्त विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें वर्तमान अवलोकन सम्बंधी सीमाओं के कारण आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। सूर्य पर किसी भी विस्फोट के न दिखने पर भी पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों का पूवार्नुमान लगाने के लिए इन 'गुप्त कोरोनल मास इजेक्शन' को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हाल ही में हुए एक अध्ययन में, खगोलविदों ने नासा के मल्टी अंतरिक्ष यान के प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए, 19 मार्च 2023 को घटी एक ऐसी ही स्टील्थ सीएमई की जांच की है। इसके कारण लगभग 3 दिन बाद पृथ्वी पर एक तीव्र तूफान आया, और चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिणी घटक और बढ़ी हुई घनत्व वाली कमजोर, स्टील्थ सीएमई के पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रभाव के प्रमाण पाए।

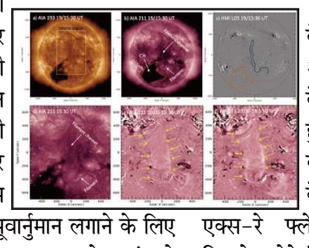

यह सीएमई सूर्य के केंद्र के पास एक अनुदैर्ध्य-फिलामेंट चैनल के विस्फोट से उत्पन्न हुआ। आम तौर पर होने वाले शक्तिशाली सीएमई के विपरीत, इनके साथ एक्स-रे फ्लेयर्स और/या रेडियो विस्फोट होते हैं, यह घटना इन मानक सौर चेतावनी संकेतों के बिना घटी और इस कराण असाधारण रूप से मायावी बन गई।

इस गुप्त सीएमई का अध्ययन सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के शोधकताओं द्वारा किया गया है। आईआईए के प्रमुख लेखक पी. वेमारेड्डी ने बताया, "इस तरह के कमजोर सीएमई सूर्य पर कोई भी पता लगाने योग्य संकेत नहीं छोड़ते हैं और इसलिए वर्तमान अवलोकन क्षमता के साथ इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल है।" उन्होंने नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी (एसडीओ), सोलर ऑर्बिटर (सोलो), स्टीरियो-ए और विंड सहित कई अंतरिक्ष यानों से प्राप्त डेटा का उपयोग किया।

एसडीओ से प्राप्त अत्यधिक पराबैंगनी छवियों से सीएमई स्रोत क्षेत्र के पास एक कोरोनल होल की उपस्थिति का पता चला। जब सीएमई इन कोरोनल होल के निकट विस्फोट करते हैं, तो वे अक्सर तीव्र सौर पवन द्वारा दूर ले जाए जाते हैं।

बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी ने बनाया सॉलिड प्लान, 'दीदी' को मात देने के लिए नई रणनीति

(एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर इस बार पूरे देश की नजर है। ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जबकि बीजेपी के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। 2011 से ममता बनर्जी लगातार सत्ता पर काबिज हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी उन्हें उखाड़ नहीं पाई है। इस बार बीजेपी ने बंगाल फतह करने के लिए सॉलिड रणनीति बनाई है। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि दीदी (ममता बनर्जी) पर सीधे हमले नहीं किए जाएंगे

आने वाले तीन महीने न सिर्फ चुनावी गणित तय करेंगे, बल्कि यह देश की राजनीति के लिए भी निर्णायक माने जा रहे हैं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी चुनावी रणनीति के केंद्र में हिंदुत्व के साथ-साथ महिला सुरक्षा, घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे होंगे। बीजेपी का फोकस ममता बनर्जी

के बजाय टीएमसी की भ्रष्ट संस्कृति और शासन रहने वाले हैं।

3 महीने तक सिलसिलेवार चलेगा प्रचार

पार्टी नेतृत्व ने अगले तीन महीनों के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की है। पार्टी का मानना है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये तीन महीने बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीन महीनों की तैयारी से ही बंगाल की सत्ता की दिशा तय होगी। फरवरी का महीना संगठनात्मक मजबूती के लिए अहम माना जा रहा है। इस दौरान बूथ स्तर पर किए गए काम को ही सत्ता तक पहुंचने की नींव बताया जा रहा है।

राज्य में दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के कारण फरवरी को 'साइलेंट पीरियड' माना जाता है। इस दौरान लाउडस्पीकर और बड़ी रैलियों पर पाबंदी रहती है। परीक्षाओं को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां भी सीमित कर दी जाती हैं। बीजेपी ने इस समय का इस्तेमाल करने के लिए भी रणनीति बना ली है। साइलेंट पीरियड का इस्तेमाल संगठन को मजबूत करने में किया जाएगा। फरवरी में बूथ कमेटियों का पुनर्गठन, कार्यकताओं की जिम्मेदारियां तय करना, डोर-टू-डोर अभियान, छोटी बैठकों और संवाद जैसे पारंपरिक प्रचार तरीकों पर जोर दिया जाएगा।

इखढ की नजर वोटर लिस्ट संशोधन पर

- बीजेपी की नजर वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (रक्क्र) पर भी टिकी है। 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पार्टी बूथ स्तर पर गहन समीक्षा शुरू करेगी।

जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई के आधार वर्ष संशोधन पर तीसरी प्री-रिलीज परामर्श कार्यशाला का आयोजन 30 जनवरी 2026 को चेन्नई में किया

(एजेंसी)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 30 जनवरी 2026 को चेन्नई में सकल घरेलू उत्पाद (GDP), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार वर्ष संशोधन पर तीसरी रिलीज-पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। पहली रिलीज-पूर्व परामर्श कार्यशाला 26 नवंबर 2026 को मुंबई में और दूसरी 23 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

इन कार्यशालाओं का प्राथमिक उद्देश्य हितधारकों के साथ प्रस्तावित पद्धतिगत और संरचनात्मक सुधारों को साझा करके पारदर्शिता को मजबूत करना, सूचित संवाद को बढ़ावा देना और GDP, IIP और CPI की संशोधित श्रृंखला जारी करने से पहले व्यापक परामर्श सुनिश्चित करना था। वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानकर GDP और IIP की नई श्रृंखला क्रमशः 27 फरवरी 2026 और 28 मई 2026 को जारी होने वाली है, जबकि आधार वर्ष 2024 वाली CPI की नई श्रृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की शोभा डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर; प्रो. राजीवा लक्ष्मण करंदीकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, MoSPI; डॉ. सौरभ गर्ग, सचिव, MoSPI; डॉ. शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और श्री एन. के. संतोषी, महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी) सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ाई। कार्यशाला में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें प्रख्यात अर्थशास्त्री, आरबीआई, बार्कलेज बैंक पीएलसी और गोल्डमैन सैक्स जैसे वित्तीय संस्थानों के विशेषज्ञ, विषय-विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सी आर राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जैसे संस्थान, नीति आयोग जैसे थिंक टैंक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

स्वागत भाषण में, श्री एन. के. संतोषी, महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी), MoSPI ने मुख्य अतिथि डॉ. सी. रंगराजन और गणमान्य व्यक्तियों के प्रति कार्यशाला में आने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने GDP, CPI और IIP की नई श्रृंखला और आधार वर्ष संशोधन के लिए की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया और उल्लेख किया कि यह अभ्यास व्यापक पद्धतिगत समीक्षा, अद्यतन वर्गीकरण और विस्तृत परामर्श के बाद किया गया है।

मुख्य अतिथि डॉ. सी. रंगराजन ने आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को मजबूत करने के लिए डेटा उपयोगकताओं और हितधारकों को जोड़ने के महत्व पर जोर दिया और रिलीज-पूर्व परामर्श कार्यशाला को इस दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने भारत के आर्थिक संक्रमण पर नजर रखने के लिए सटीक, समयबद्ध और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ डेटा की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए ऋद्धढ श्रृंखला में संशोधन आवश्यक हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आधार संशोधन में नए डेटा का उपयोग, पारदर्शी कार्यप्रणाली और डेटा की सटीक व्याख्या से आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता और उपयोगिता मजबूत होगी।

डॉ. सौरभ गर्ग, सचिव, टङ्मरढकने कार्यशाला का संदर्भ प्रस्तुत किया और प्रभावी नीति निर्माण के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया, तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए समयबद्ध, विस्तृत (ॅल्ल४'१) और उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा प्रसार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैकल्पिक डेटा स्रोतों का लाभ

ओलंपिक आंदोलन में योगदान देने के लिए भारत की रणनीति, योजना एवं दृष्टिकोण से प्रभावित: माकिस असिमाकोपुलोस, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने खेल शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेल का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और देश में ओलंपिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले विशेषज्ञों का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है: हरि रंजन राव, खेल सचिव, भारत सरकार

(एजेंसी)।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी (आईओए) के निदेशक श्री माकिस असिमाकोपुलोस और सुश्री एलेक्जेंड्रा कारास्कौ के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय का दौरा किया, जिसका नेतृत्व श्री हरि रंजन राव, सचिव, खेल मंत्रालय ने किया।

बैठक के दौरान श्री असिमाकोपुलोस ने कहा कि वह "खेल मंत्रालय द्वारा ओलंपिक आंदोलन में योगदान देने के लिए भारत की रणनीति, योजना एवं दृष्टिकोण" से बहुत प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी खेल कार्यक्रमों का अवलोकन करने के बाद, आईओए भारत में ओलंपिक शिक्षा को मजबूत करने में सहयोग करने के लिए उत्सुक है।

उन्होंने आगे कहा, "हम खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लोगों को ओलंपिज्म एवं ओलंपिक खेलों के मूल्यों के बारे में प्रशिक्षित करने के

लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहते हैं ताकि भारतीय युवा ओलंपिक मूल्यों को समझ सकें।"

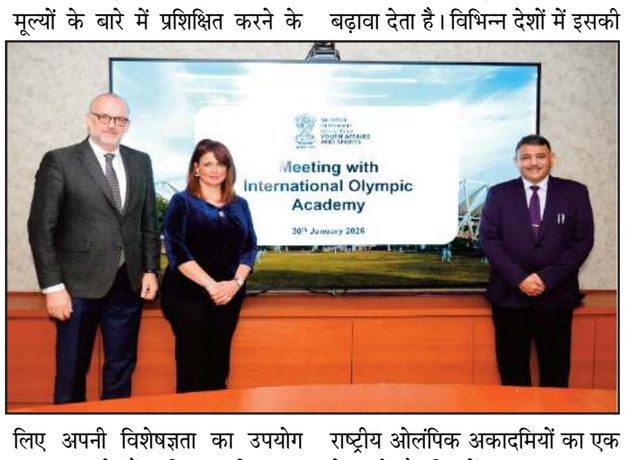

इस बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी एवं खेल मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय ओलंपिक संघ और नव पुनर्जीवित राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के बीच सहयोग पर चर्चा करना था जिससे भारतीय प्रशिक्षकों, खेल विज्ञान विशेषज्ञों एवं शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों द्वारा भारत में खेल शिक्षा को मजबूत किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक (आईओए) की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो ओलंपिक शिक्षा एवं अध्ययन को बढ़ावा देता है। विभिन्न देशों में इसकी राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमियों का एक नेटवर्क है जिसमें भारत का एक अकादमी भी शामिल है जिसे हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है।

इस विषय पर आगे बात करते हुए सुश्री एलेक्जेंड्रा ने कहा, "हमारे बीच बहुत सार्थक चर्चा हुई एवं खेल सचिव की प्रस्तुति से हमें पता चला कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी और 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को लंबे समय बाद पुनर्जीवित किया गया है और हम भारत में ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आईओए एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं।"

बैठक के निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करते हुए खेल सचिव श्री हरि रंजन राव ने कहा, "हमारी पहली बैठक बहुत सफल रही और हम इस सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी (आईओए) के समृद्ध अनुभव से लाभ उठा सकें तथा अपनी खेल शिक्षा को और मजबूत कर सकें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेल पारिस्थितिकी तंत्र बहुत तीव्र गति से विकसित हो रही है और भारत में ओलंपिक आंदोलन को आगे ले जाने वाले विशेषज्ञों का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

श्री राव ने आगे कहा कि आईओए भारत के लिए वैश्विक मानक पाठ्यक्रम बनाकर, भारत के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करके, प्रशासकों के लिए प्रमाणित पाठ्यक्रम बनाकर, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा मास्टरक्लास आयोजित करके तथा संयुक्त अनुसंधान एवं डिजिटल सहयोग के माध्यम से भारत के ओलंपिक शिक्षा प्रयासों का समर्थन कर सकता है।

भारत पर्व 2026 में पंजाबी लोक आर्केस्ट्रा और कलंदरी धमाल के साथ जीवंत होगी पंजाब की संगीत विरासत

(एजेंसी)।

नई दिल्ली के एतिहासिक लाल किले में आयोजित होने वाले 'भारत पर्व 2026' में पंजाब की समृद्ध संगीत और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। 31 जनवरी 2026 को पंजाबी लोक ऑर्केस्ट्रा और कलंदरी धमाल की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

पंजाबी लोक ऑर्केस्ट्रा एक अनूठा समूह है, जिसे ढोल, ढोलकी, ताल-कोजे, तंसारी, बांसुरी, नगाड़ा, चिमटा, सप, कड़ा और वंजली जैसे पारंपरिक पंजाबी लोक वाद्ययंत्रों के विस्तृत चयन के साथ तैयार किया गया है। यह ऑर्केस्ट्रा लयबद्ध, सुरीले और तालबद्ध लोक वाद्ययंत्रों को एक एकल, संरचित संगीतमय प्रस्तुति में पिरोता है। पारंपरिक पंजाबी लोक धुनों को ऑर्केस्ट्रा के लिए बहुत ही सोच-समझकर रचा और व्यवस्थित किया गया है, जिससे उनकी मौलिक लोक आत्ा मा को संरक्षित रखते हुए उन्ा हें एक सामूहिक और सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

इस ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन बारह छात्रों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट वाद्य यंत्र बजाने की भूमिका निभाता है। उनका प्रदर्शन टीमवर्क, समन्वय और पंजाबी लोक संगीत परंपराओं की गहरी समझ

को उजागर करता है। यह पहल न केवल पंजाबी लोक संगीत के संरक्षण में योगदान देती है, बल्कि छात्रों को समूहिक प्रदर्शन और लोक वाद्योजन तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है।

इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक आयाम जोड़ते हुए सिंध और पंजाब के पारंपरिक सूफी लोक नृत्य 'कलंदरी धमाल' की भी प्रस्तुति होगी। कलंदरी धमाल एक भक्तिमय नृत्य है, जो ईश्वर और सूफी संतों के प्रति प्रेम और समर्पण को व्यक्त करता है और विशेष रूप से सेहवान शरीफ स्थित लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह से जुड़ा है।

इस प्रस्तुति में ढोल, घड़ियाल, सोरना, शंख और तुम्बा जैसे वाद्ययंत्रों द्वारा निर्मित ओजपूर्ण संगीत होता है, जिसके साथ तालियों की गडगड़ाहट और "दमदम मस्त कलंदर" जैसे भक्तिपूर्ण जयकारे गूंजते हैं। ऊर्जावान ताल नृतकों को एक आनंदमय और आध्यात्मिक अवस्था में ले जाती है। इसकी मुद्राएं स्वतंत्र और अभिव्यंजक होती हैं, जिनमें नृतक लय पर घूमते, पैर थपथपाते और झूमते हैं। कई नृतक नंगे पैर और भारी धुंधरू पहनकर नृत्य करते हैं, जो विनम्रता और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है।

कलंदरी धमाल आध्यात्मिक स्वतंत्रता, प्रेम, एकता और भक्ति का प्रतीक है, जो जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की सीमाओं से परे है। संगीत और नृत्य के माध्यम से यह शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का एक शक्तिशाली संदेश फैलाता है।

पंजाबी लोक ऑर्केस्ट्रा और कलंदरी धमाल की ये संयुक्ा त प्रस्ा तुतियां कल आयोजित होने वाले 'भारत पर्व 2026' में दर्शकों को पंजाब की जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक गहन अनुभव प्रदान करने का वादा करती हैं।